भावी जनज्वार की अगवानी की तैयारी करो

कुछ अपरिहार्य विवशताओं के कारण 'आह्वान' का यह अंक एक अंक (अप्रैल-जून 2000) के अंतराल के बाद पाठकों तक पहुंच रहा है। एक पाक्षिक बुलेटिन के रूप में 1991 में प्रकाशन की शुरुआत से लेकर अनेक सीमाओं-समस्याओं-अवरोधों को पाठकों-मित्रों-शुभचिन्तकों के सहयोग के दम पर पार करते हुए हमने यह यात्रा आज तक जारी रखी है। 'आह्वान' टीम के पुनर्संगठन की जिन कोशिशों के तहत हमने नियमित पाक्षिक अखबार के स्थान पर एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में इसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया था, वह प्रक्रिया अभी भी जारी है। पत्रिका के एक अंक का अन्तराल भी इसी वजह से हुआ। लेकिन, हमें पूरा विश्वास है कि जनसंसाधनों और जनशक्ति में अडिग आस्था के बूते पर हम 'आह्वान' के त्रैमासिक स्वरूप को नियमित बनाते हुए पाक्षिक अखबार के मूल स्वरूप को फिर से बहाल कर पायेंगे। जिस जरूरत के अहसास के साथ एक पाक्षिक के रूप में 'आह्वान' की शुरुआत हुई थी आज वे जरूरतें नये सिरे से एक ऐसे नियमित अखबार के प्रकाशन की मांग कर रही हैं जो व्यापक छात्र-युवा आबादी के बीच परिवर्तनकामी विचारों के प्रचार-प्रसार का मजबूत संवाहक बने।

'आह्वान' के प्रवेशांक (7-21 अगस्त 1991) में हमने लिखा था : **''आज हमारा देश आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ता और ठहराव के जिस मुकाम पर पहुंच चुका है वहां से एक सर्वव्यापी-सर्वग्राही सामाजिक क्रान्ति का प्रबल वेगवाही प्रवाह ही उसे आगे बढ़ा सकता है। और हमेशा की तरह खतरों-चुनौतियों और कुर्बानियों से भरी इस जिम्मेदारी का दायित्व इतिहास ने छात्रों-नौजवानों के कन्धों पर सौंपा है। और इस दायित्व को पूरा करने के लिए सामाजिक परिवर्तन की प्रबल इच्छाशक्ति के साथ दृढ़ निश्चय और संकल्पशक्ति के धनी छात्रों-युवाओं को आगे आना होगा। समाज में एक नये सामाजिक नवजागरण और प्रबोधन का बिगुल फूंकना होगा। निराशा और पस्तहिम्मती में पड़े हुए सुषुप्त समाज में एक नयी आशा, नयी जागृति और नयी प्रेरणा का संचार करना होगा। बहुविध और बहुआयामी राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक सक्रियताओं में प्रत्यक्ष शिरकत करते हुए युवाओं को स्वयं को सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी उपकरण के रूप में विकसित करते हुए पूरे समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का उन्नयन करने का जटिल और खतरों से भरा, लेकिन अपरिहार्य गुरुतर दायित्व पूरा करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। आह्वान कैम्पस टाइम्स इस जरूरत के अहसास से निकलने वाली अपनी भूमिका को पूरी संजीदगी के साथ निभाने का निरन्तर प्रयास करता रहेगा और इस दिशा में छात्रों-युवाओं का प्रयासों का सहभागी बनेगा।''**

यह था हमारा अहसास, जिसकी जमीन पर खड़े होकर हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। आठ वर्ष से भी अधिक समय के सफर के दौरान हमें ढेरों नये हमसफर मिले हैं। इसने हमारे संकल्पों को लगातार मजबूत बनाया है। लेकिन, हम किसी प्रकार की आत्मतुष्टि का शिकार हुए बिना यह महसूस करते हैं कि हमें अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। हमें और अधिक सृजनात्मकता के साथ अपने दायित्व को पूरा करना होगा और अपने हमसफरों का दायरा और अधिक तेजी के साथ बढ़ाना होगा।

हां, निस्सन्देह हमें अपनी तैयारियों को तेज कर देना होगा क्योंकि समाज के अन्तस्तल में दाब तेजी से बढ़ता जा रहा है जो आने वाले प्रचण्ड ज्वार का पूर्वसंकेत है।

अपनी ओर से

अपने संकटों से उत्पन्न मजबूरियों से देश के सत्ताधारी आत्मघाती डगर पर आज काफी दूर निकल आये हैं जहां से पीछे लौटना अब न तो उनकी चाहत है और न ही अब यह सम्भव है। आर्थिक ''सुधारों'' के दूसरे दौर में निजीकरण-उदारीकरण की अभूतपूर्व विनाशलीला रचने पर वे आमादा हो चुके हैं। बीमा क्षेत्र के बाद अब अर्थव्यवस्था के बचे-खुचे क्षेत्रों-बैंकिंग, ऊर्जा, संचार, परिवहन, कोयला, इस्पात, सिंचाई आदि क्षेत्रों को देशी-विदेशी निजी पूंजीपति लुटेरों को सुपुर्द कर देने की दिशा में कदम बढ़ा दिये गये हैं। विरोध को कुचलने-दबाने की रणनीति भी बना ली गयी है। कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ-साथ जबरिया छंटनी का नया सिलसिला शुरू होगा। एक बार फिर न्यायपालिका ने शासक वर्ग के प्रति पूरी वफादारी दिखाते हुए सरकारी प्रतिष्ठानों के ''फालतू'' कर्मचारियों को निकाल बाहर करने का फैसला भी सुना दिया है। इस हथियार के मिलते ही अब सरकारी विभागों में ''फालतू'' कर्मचारियों की सूचियां बननी शुरू भी हो चुकी हैं। इन सब हथकण्डों के बाद अन्तिम हथियार तो सुरक्षित ही हैं-लाठी, गोली, जेल।

इसके साथ ही निजी पूंजीपतियों के हाथ खुले कर देने वाला नया श्रम कानून भी लागू होने में अब सिर्फ तकनीकी अड़चनों के दूर होने की देर है। अब कारखाना मालिक जब जरूरत होगी मजदूरों को काम पर रखेंगे। जरूरत खत्म तो निकाल बाहर करेंगे। काम के घण्टे, सेवा शर्तों आदि को तय करने में भी उन्हें काफी छूटें मिल जायेंगी। मजदूरों-मालिकों के बीच किसी विवाद में अब सरकार बीच में नहीं पड़ेगी। कई ऐसे विशेष औद्योगिक क्षेत्र होंगे जहां किसी किस्म के श्रम कानून लागू ही नहीं होंगे। नये श्रम कानून की यही मुख्य बातें हैं। जाहिर है श्रमिकों के शोषण-उत्पीड़न का जो नया दौर शुरू होगा उसकी तुलना अब सिर्फ आरम्भिक पूंजीवाद के बर्बर दिनों से ही की जा सकती है।

इतना ही नहीं, राज्य द्वारा प्रदत्त सीमित जनसुविधाओं में कटौतियों का सिलसिला भी और तेज हो गया है। वर्ष 1999-2000 के बजट में उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में व्यापक कटौतियों और केन्द्र व राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों पर ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कटौती के बाद अब सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों के विभिन्न शुल्कों में भी भारी बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। बची-खुची सुविधाओं पर भी कुठाराघात कर बाजार की शक्तियों के खुले खेल की सारी बाधाओं को दूर करने की सरकार बन चुकी है।

नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शिक्षा के बाजारीकरण की मुहिम भी तेज हो गयी है। केन्द्र और राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों-कालेजों में मौजूदा सत्र में एक बार फिर भारी शुल्क वृद्धि और सीटों में कटौती कर लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं। समूची शिक्षा व्यवस्था को देशी-विदेशी पूंजीपतियों की भूमण्डलीकरण की नयी जरूरतों के अनुसार बदलने की प्रक्रिया तेज हो गयी है।

शिक्षा व्यवस्था शासक वर्ग की जरूरतों को पूरा करने का एक उपकरण ही होती है। पुरानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार खड़ा किया गया शिक्षा का ढांचा अब शासक वर्गों की नयी जरूरतों के लिए पुराना पड़ गया है। अब पुराने किस्म के डाक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन, प्रबन्धक, प्रशासक, शिक्षक और बाबू मौजूदा 'साइबर युग' के साथ मेल नहीं खा सकते। अब नये किस्म के कल-पुर्जों को तैयार करने के लिए 'शिक्षा के कारखानों' का नवीनीकरण करना जरूरी है। अब मानवीय संवेदना, जनतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सरोकारों से रहित आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी, निरंकुश सर्वसत्तावादी मूल्यों से लैस बाजारू किस्म के नये मानव संसाधन चाहिए। इसलिए, पाठ्यक्रमों में व परीक्षा प्रणाली में हर स्तर पर फेरबदल किये जा रहे हैं। राज्य मशीनरी के सर्वाधिक वफादार एवं कुशल कल-पुर्जों की भर्ती करने वाली संस्था संघ लोक सेवा आयोग ने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में ''गुणात्मक'' फेरबदल करने का निर्णय लिया है।

शासक वर्ग के चौतरफा हमलों से जो परिदृश्य निर्मित हो रहा है उससे अब ''सुधारों'' को लेकर कोई भी भ्रम आम जनता के किसी भी हिस्से में नहीं रह गया है। कारखानों-दफ्तरों से ठेलकर सड़कों पर खड़े कर दिये कर्मचारी-मजदूर, तबाह-बरबाद हो रहे किसान और स्कूलों-कालेजों-विश्वविद्यालयों से धकियाकर भविष्य की अंधेरी सुरंग में पहुंचा दिये जा रहे मेहनतकशों के बेटे-बेटियां अब बहुत दिनों तक अपनी-अपनी पीड़ाओं को जज़्ब किये खामोश नहीं बैठेंगे। यह चुप्पी टूटेगी। निश्चय ही। आज की खामोशी और यह घुटन आने वाले ज्वार की आहट है। यह कोरा आशावाद नहीं। समाज की अन्दरूनी हलचलों को महसूस करने वाले लोगों के लिए इस नतीजे पर पहुंचना कठिन नहीं है। पहले के समयों में ऐसा ही हुआ है, आज भी यही होने वाला है।

भविष्य को इस आहट को शासक वर्ग भांप चुका है। आखिर उसके पास भी इतिहास का निचोड़ मौजूद है।

जनता की रक्तमज्जा तक निचोड़ लेने के बावजूद शासक वर्ग आज अपने संकटों को दूर नहीं कर पा रहा है। अर्थव्यवस्था का ठहराव बदस्तूर जारी है। सूचना, संचार और मनोरंजन उद्योग के नये सम्भावनायुक्त क्षेत्रों को अधिकतम सीमा तक निचोड़ लेने के बावजूद पूंजीवाद के बुनियादी संकट—मुनाफे की वृद्धि दर बढ़ने और बाजार के लगातार विस्तार का संकट—का कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं सूझ रहा है। शेयर मार्केट में रह-रहकर आने वाली उछालों और सिर्फ अल्पकालिक राहतों से पैदा हुई खुशी अगले ही पल मायूसी में बदल जाती है। ऐसे में, अपने संकटों का और अधिक बोझ आने वाले दिनों में जनता पर लादना उसकी मजबूरी है। इसके फलस्वरूप जनअसन्तोष का घनीभूत होना और उसका विस्फोट करना भी लाजिमी है। इसीलिए, शासक वर्ग आज अपने दमन तंत्र को भी चाक-चौबन्द कर रहा है।

आज की खामोशी और यह घुटन आने वाले ज्वार की आहट है। यह कोरा आशावाद नहीं। समाज की अन्दरूनी हलचलों को महसूस करने वाले लोगों के लिए इस नतीजे पर पहुंचना कठिन नहीं है। पहले के समयों में ऐसा ही हुआ है, आज भी यही होने वाला है।

तमाम बुर्जुआ पत्र-पत्रिकाओं, उदारवादी बुर्जुआ जनों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक के विरोध के बावजूद नये खतरनाक आंतकवाद विरोधी कानून ('टाडा' के स्थान पर नया 'पोटा' कानून) को किसी भी कीमत पर लागू करने की सरकार की जिद के पीछे यही कारण है। कौन नहीं जानता कि 'टाडा' ('टेररिस्ट एण्ड डिसरप्टिंग एक्टिविटीज') व 'रासुका' (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) जैसे कानूनों का उपयोग किसके खिलाफ किया जाता है। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जनसंघर्षों से जुड़े कार्यकर्ताओं, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, पत्रकारों एवं जनतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं पर ही इनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता रहा है, यह सर्वविदित है। अमेरिकी खुफिया विभाग (एफ.बी.आई.) का देश में दफ्तर खोलना, राजनीतिक हत्याओं में माहिर कुख्यात इस्रायली खुफिया एजेंसी 'मोसाद' के तजुर्बों व कार्यप्रणाली से सीखने की तत्परता व आन्तरिक सुरक्षा पर खतरों की चीखपुकार, पुलिस अधिकारियों को विदेशों में भेजकर प्रशिक्षण दिलवाना आदि शासक वर्ग की तैयारियों के ही उदाहरण हैं।

जाहिर है, शासक वर्ग आकलन कर चुका है कि आने वाले दिनों में उसे प्रचण्ड जनज्वारों से लोहा लेना है। इसलिए वह अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसलिए, हमें भी निश्चिन्त नहीं बैठना चाहिए। हमें भी अपनी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए।

इसलिए, हम सभी बहादुर, मुक्तिचेता नौजवानों का आह्वान करते हैं कि वे भावी जनज्वार की अगवानी की तैयारी करने में जुट जायें। ●